SHRI R. VENKATARAMAN: What was stated in the House was that over a period the difference between the pensions had been narrowed down and today the difference is hardly Rs. 24 whereas it had been something like Rs. 60—70 earlier. That is why we have said that we have done everything possible to narrow the difference between the new pension rates and the old pension rates.

Functioning of Mohini Mills in West Bengal

*383. SHRI RAM SWARUP RAM: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of India have nationalised Mohini Mills in West Bengal recently;

(b) whether he is aware of the reports that the mode of functioning of the mills after nationalisation has not been satisfactory; and

(c) if so, what is the reaction of Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI SHIVRAJ V. PATIL): (a) No, Sir.

(b) an (c). Do not arise.

श्री राम स्वरूप राम: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का जो जवाब मिल रहा है इससे ऐसा लग रहा है कि मंत्री जी अपने विभाग से काफ़ी इनइनफ़ोर्म्ड हैं, इनको सूचना नहीं है कि इनके विभाग में क्या हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : अनभिज्ञ हैं ।

श्री राम स्वरूप राम : मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वेस्ट बंगाल में मोहिनी मिल्स को टेक्साइल्स कारपोरेशन ने सितम्बर, 1981 में लिया था, उस समय के तत्काल मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी ने टेक ओवर किया था, और उस मिल के मौडर्नाइजेशन के नाम पर 98 लाख रु० की राशि आवंटित की गई । और मंत्री जी कहते हैं कि हमें कोई जानकारी नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : दरअसल बात यह है कि मोहिनी मिल्स ने मिनिस्टर साहब को मोहित नहीं किया है ।

श्री राम स्वरूप राम : तो मैं पुनः मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मेरे प्रश्न की गम्भीरता को समझते हुए अपने जवाब को पहले इन्हें वापस लेना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछें कि वापस लेंगे कि नहीं ।

श्री राम स्वरूप राम : आप जानते हैं कि भारत सरकार की नीति है कि सिक यूनिट या बन्द मिलों को नेशनलाइज़ करके रोज़गार की गारण्टी देती है । एन० टी० सी० में 111 मिल्स हैं और उनको टेक ओवर कर लिया गया है और इसी नीति के तहत मोहिनी मिल्स को भी इन्होंने सितम्बर, 1981 में टेक ओवर किया जो कि वेस्ट बंगाल की सब्सिडियरी मिल है जिसमें 18 मिलें हैं जिनमें गया में गया काटन मिल, मुकामा में स्पिनिंग मिल और पश्चिम बंगाल में और कई मिलें हैं जिनमें से यह मोहिनी मिल्स भी है, और वहां पर इन्होंने ऐग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर** को रखा है जो एक डिसमिस्ड पदाधिकारी है जिसको भारत सरकार ने गम्भीर आरोप में डिसमिस किया है । . . . .

MR. SPEAKER. Names need not be mentioned.

**Not recorded

ऐसे पदाधिकारियों को ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाये हुए हैं और उनके हाथ में 98 लाख रुपये की राशि दे रखी है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल तो कर नहीं रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं ।

श्री राम स्वरूप राम : बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । क्योंकि 250 करोड़ रुपये के घाटे में एन० टी० सी० चल रही है, इसलिए भूमिका तो बांधना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : भूमिका बांधने के लिए प्रश्न-काल नहीं होता ।

श्री राम स्वरूप राम : प्रश्न ही पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछ लीजिए, वरना उससे भी छुट्टी हो जायेगी ।

श्री राम स्वरूप राम : मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि पुनः अपने विभाग को देखें, उनके विभाग के पदाधिकारियों ने उनको मिस-लीड किया है ।

क्या सरकार की जानकारी में यह है कि सिक मिल में माडर्नाइज करने के लिए अहमदाबाद की ऐसी कम्पनी से मशीनें खरीदी जाती हैं जो मशीन सब-स्टैंडर्ड हैं और माडर्नाइज़ेशन के नाम पर करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है ? कहां से मशीनें खरीदी जाती हैं, इसी को बात बता दी जाये ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : माननीय सदस्य को थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, वह मुझे सबसे पहले दूर करनी पड़ेगी । जब किसी मिल को हम नेशनलाइज़ करते हैं तो उसका एक प्रोसीजर होता है । हम ऐसा तय कर लेते हैं कि 6 महीने के अन्दर वह नेशनलाइज़ हो सकती है तो इन्सपैक्शन कर के उस को ले लें । यह देखने के बाद अगर नेशनलाइज़ करनी है तो ले लेते हैं, नहीं तो नहीं लेते हैं । मोहिनी मिल में ऐसा हुआ है कि इस प्रकार का नियम होने के पश्चात भी सोशल ओबलीगेशन लेने कि दृष्टि से ऐसा तय कर लिया गया कि हम इस मिल को लेंगे और देखेंगे कि अच्छी तरह से चल सकता है या नहीं चल सकती है और 6 महीने के बाद अगर लेना और नेशनलाइज़ करना जरूरी नहीं हुआ तो उसको वापिस करने के लिए कैबिनेट में तय कर के इस मिल के सम्बन्ध में कदम उठाया गया । यह मिल नेशनलाइज़ हुआ है, यह समझना गलत है । यही उत्तर में हमने बताया भी है और यह मालूमात माननीय सदस्य के दृष्टि में न होने से शायद वह ऐसा समझ रहे हैं कि हम गलत जवाब दे रहे हैं । असल में यह गलत जवाब नहीं है ।

दूसरा जो प्रश्न उन्होंने उठाया है कि किसी और से माइनर्नाइजेशन के और दूसरे तरीके से लेने के लिए, उसके लिए मुझे नोटिस चाहिए । उसमें देखने के बजाय मैं जवाब दे दूं तो यह गलत हो जायेगा ।

श्री राम स्वरूप राम : माननीय मंत्री जी टेक-ओवर और नेशनलाइज़ेशन में हमको फर्क बतला रहे थे । इस बात को मैं समझ रहा हूं, लेकिन एक चीज़ वह यह बतायें कि अभी उन्होंने कहा कि कुछ ओब्लीगेशन का टैक्नीकल टर्म, मुझे पता नहीं वह क्या है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं अपने विद्वान मंत्री जी से कि आपने जो देखने के लिए लिया कि टेक-ओवर किया जाये या नहीं तो किन पदाधिकारियों के साथ आपने मिल का जिम्मा दिया है

क्या ऐसा नियम रखा गया है कि वेस्ट बंगाल सब्सीडियरी के अन्तर्गत जो मिल पड़ते हैं उसका एक चेयरमैन होता है, और इसके चेयरमैन कलकत्ते में बैठते हैं क्योंकि मोहिनी मिल भी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसलिए उस के चेयरमैन की देखरेख में सारी बातें होनी चाहिऐ थीं। आपने मिल की स्थिति को देखने के लिए, टेक-ओवर करें या न करें, यह आपकी पालिसी है, लेकिन 98 लाख रुपया वैसे पदाधिकारी को, जो चेयरमैन के अधिकारों को एन्क्रोच कर के आया है, उसे दिया है। यह तो एन्क्रोचमैंट आफ राइट्स है जो कि नियम और प्रोसीजर में बने हुए हैं। आप उसके बारे में बतावें।

दूसरी चीज यह बतायें कि होल्डिंग कम्पनी में 250 करोड़ का घाटा है, यह कम घाटा नहीं है। इसकी वजह यह है कि होल्डिंग कम्पनी में ऊपर से ले कर नीचे तक मैल- प्रैक्टिस है, जो मशीन माडर्नाइजेशन के नाम पर पैसे लिये जाते हैं ....

अध्यक्ष महोदय : सवाल कर लीजिए, आप तो हरेक बात पर लेक्चर कर लेते है।

श्री राम स्वरूप राम : सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, आपके बोलने से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने 98 लाख रुपया किस पदाधिकारी की देख-रेख में मोहिनी मिल का स्टडी के लिए दिया है। दूसरे, एन० टी० सी० जो 250 करोड़ रुपये के घाटे में चल रहा है, उसको देखते हुए क्या सरकार मैनेजिंग डायरेक्टर के विरुद्ध कोई सख्त कार्यवाही करेगी ; अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कई प्रश्न किए हैं और उनके बारे में मेरे पास कागज में पूरी मालूमात आने के बगैर मेरे लिए उनका उत्तर देना उचित नहीं होगा, क्योंकि इसको ले कर कल प्रिविलेज मोशन आ सकता है।

जहां तक एन०टी०सी० के कार्य का सवाल है मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि एन०टी० सी० के पास जो भी मिलें आई हैं, वे ऐसी मिलें हैं, जो बन्द थीं—बन्द ही नहीं, बल्कि कुछ मिलों में मशीनों पर मिट्टी गिरी हुई थी और उसमें झाड़ उगे हुए थे। वहां के लोगों को काम देने के लिए और प्रोडक्शन चालू रखने के लिए एन०टी०सी० ने वे मिलें लीं और हम उन्हें चला रहे हैं। मेरा निवेदन यह नहीं है कि वहां पर जो कुछ हो रहा है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं होगा, परन्तु यह बात हमेशा ध्यान में रखना जरूरी होगा कि जो मिलें नहीं चल सकता थीं, जो बन्द पड़ी हुई थीं, ऐसी मिलों को ले कर हम काम चला रहे हैं।

इसके अलावा हम एन०टी०सी० की तरफ से कण्ट्रोलल्ड क्लाथ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो दूसरी मिलें बनाने के लिए तैयार नहीं थीं। माननीय सदस्य ने जो सवाल किसी 98 लाख रुपये और किसी अफ़सर के बारे में पूछा है, उसके बारे में पूरी मालूमात लिए बगैर कुछ कहना उचित नहीं होगा।

श्री राम स्वरूप राम : जांच तो करवा दीजिए। (व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा भूमिका दे कर मस्तिष्क पर बोझ नहीं डालना चाहती। मैं दो बातें पूछना चाहती हूं। क्या मंत्री महोदय की इस बात की जानकारी है कि उस मिल के

चीफ एक्सीक्यूटिव आफ़िसर डिसमिस्ड हैं और फिर भी वह कार्यरत हैं ; यदि वह कार्यरत हैं, तो वह किस प्रकार और किस परिस्थिति में कार्यरत हैं ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मुझे इस सम्बन्ध में अभी कोई जानकारी नहीं है । लेकिन मैं उसकी जानकारी ले कर माननीय सदस्या को दे दूंगा ।

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Regarding Mohini mill, our ex-Finance Minister knows better, because he was dealing with it. I am sorry—I mean Shri Pranab Mukherjee, who, was our ex-Commerce Minister.

MR. SPEAKER: I thought he was referring to Mr. Venkataraman.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): He has already made me ex-Finance Minister, by putting his axe on me!

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Someday you will be axed, no doubt! About Mohini mill, it was actually taken over in September, as my hon. friend said. According to the conditions explained by the Minister, they will watch the development for six months and then they will decide whether it should be nationalised or not. But already six months have passed. I personally know because I made representations to Mr. Pranab Mukherjee that for several months after starting the work, the work completely stopped because there was no financial payment from the banks. I approached him. He said "I will help". But only very recently, nearly 3 weeks ago he told me, "I have given clearance". Under these circumstances, the decision to nationalise should not be on the basis of that condition, namely, after seeing the performance for six months. My point is, once you take over, the next step should be nationalisation. There should not be any intermediate period, because after spending so much money, if you decide that it will be again returned back to the old owner, this is a wrong policy. It means you are giving a premium to the old owners who are responsible for the closure of this mill. The union is cooperating with the management. Regarding the efficiency of this Chief Executive Officer, there is some adverse opinion also. I fully agree with him. Under these circumstances, when you have taken over this Mohini mill after various representations, will you take all necessary steps so that the mill is in full working condition and it becomes viable, so that the next logical step will be the nationalisation and no other alternate decision must be taken? Does he know all the facts or not? I request Mr. Pranab Mukherjee to reply to this question because he knows all the details.

SHRI SHIVRAJ V. PATIL: I have explained to this hon. House that this mill is with the Government. Government has taken steps to start it. Some amount of money has also been spent. The problem with this mill is that the number of the workers is too large and because of this, the overhead charges are going to be too much. It requires rationalisation. Once we are able to rationalise the number of workers working there, it would be possible to run this mill and give employment to a majority of the workers there. It will not be proper for the Government to just take over the mills, then sustain losses and after some time, close down the mills and not be able to give employment to the workers also. From this point of view we are trying to run this mill in a manner which will help the Government to run the mill, provide the employment and if possible also to earn profit. You have just seen that complaints are made against NTC for incurring losses. Losses are incurred because there is no rationalisation and we are taking over the sick mills.